Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:3(4), March 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

समाजवादी पार्टी का उदय और उत्तर प्रदेश की सामाजिक संरचना पर उसका प्रभाव: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

उमेश चन्द्र, *शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय, श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय, लखनऊ–देवा रोड, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश*
umeshyadav4989@gmail.com

पल्लवी शर्मा, *शोध पर्यवेक्षक, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय, श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय, लखनऊ–देवा रोड, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश*

रत्नेश कुमार मिश्र, *शोध सह० पर्यवेक्षक, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीतिशास्त्र विभाग जवाहर लाल नेहरू पी.जी. कॉलेज एटा,*

सारांश

यह अध्ययन "समाजवादी पार्टी का उदय और उत्तर प्रदेश की सामाजिक संरचना पर उसका प्रभाव: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन" विषय का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करता है। शोध का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि समाजवादी पार्टी के गठन और उसके राजनीतिक विस्तार ने उत्तर प्रदेश की जातीय, सामाजिक एवं राजनीतिक संरचना को किस प्रकार परिवर्तित किया। विशेष रूप से अध्ययन में पिछड़ा वर्ग सशक्तिकरण, मुस्लिम समुदाय की राजनीतिक भागीदारी, मंडल राजनीति के प्रभाव तथा जाति बनाम विकास विमर्श का मूल्यांकन किया गया है। अध्ययन में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध पद्धति का प्रयोग किया गया है। निर्वाचन आयोग के आँकड़े, जनगणना रिपोर्ट, साक्षात्कार एवं सर्वेक्षण तथा द्वितीयक स्रोतों के आधार पर डेटा का तुलनात्मक एवं व्याख्यात्मक विश्लेषण किया गया है। निष्कर्षतः यह पाया गया कि समाजवादी पार्टी ने सत्ता-संरचना में सामाजिक प्रतिनिधित्व को विस्तारित किया, किंतु साथ ही पहचान-आधारित राजनीति के कारण सामाजिक ध्रुवीकरण की प्रवृत्तियाँ भी उभरीं।

प्रमुख शब्द : *सामाजिक न्याय, पिछड़ा वर्ग सशक्तिकरण, मुस्लिम राजनीतिक भागीदारी, मंडल राजनीति, पहचान राजनीति, जातीय पुनर्संरचना*

1. प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश भारतीय राजनीति का केन्द्रीय क्षेत्र रहा है, जहाँ सामाजिक संरचना मुख्यतः जाति, वर्ग, धर्म और ग्रामीण-शहरी विभाजन पर आधारित रही है। देश की सर्वाधिक जनसंख्या वाला यह राज्य लोकसभा की सर्वाधिक सीटें प्रदान करता है और राष्ट्रीय राजनीति की दिशा निर्धारित करने में निर्णायक भूमिका निभाता है। ऐतिहासिक रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा अन्य ऊँची जातियों का प्रशासनिक और राजनीतिक वर्चस्व रहा, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), दलित और मुस्लिम समुदाय अपेक्षाकृत सीमित प्रतिनिधित्व तक ही सीमित रहे। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस की प्रभुत्वकारी राजनीति ने सामाजिक असमानताओं को आंशिक चुनौती दी, किंतु संरचनात्मक परिवर्तन व्यापक रूप में संभव नहीं हो सका। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में सामाजिक-राजनीतिक असंतोष ने एक नए विमर्श को जन्म दिया, जिसने सत्ता-संरचना को पुनर्परिभाषित किया। **(जाफ़रलो, 2003; पाई, 2011; कुमार, 2012)**

मंडल आयोग की सिफारिशों का 1990 में क्रियान्वयन भारतीय राजनीति में निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नीति ने सामाजिक न्याय, समान अवसर और प्रतिनिधित्व के प्रश्न को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया। उत्तर प्रदेश में, जहाँ पिछड़ा वर्ग जनसंख्या का महत्वपूर्ण भाग है, इस निर्णय ने सामाजिक चेतना और राजनीतिक संगठन को तीव्र किया।

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:3(4), March 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

मंडल राजनीति ने समाजवादी विचारधारा को नई ऊर्जा प्रदान की, जिसका वैचारिक आधार राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों में निहित था। 'पिछड़ा पावे सौ में साठ' जैसे नारों ने सामाजिक समानता को राजनीतिक कार्यक्रम का रूप दिया। **(लोहिया, 1964; पाठक, 2010; मिश्रा, 2016)**

इसी पृष्ठभूमि में 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में हुआ। इस दल ने स्वयं को सामाजिक न्याय और समाजवादी परंपरा का प्रतिनिधि बताया तथा पिछड़ा वर्ग-मुस्लिम गठबंधन को संगठित किया। समानांतर रूप से बहुजन समाज पार्टी जैसे क्षेत्रीय दलों के उदय ने जाति-आधारित समूहों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान कर सत्ता-संतुलन को परिवर्तित किया। **(यादव, 2005; गुप्ता, 2016; त्रिपाठी, 2018)**

समाजवादी पार्टी का उदय केवल राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि सामाजिक संरचना में परिवर्तन का संकेत था। पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण, मुस्लिम समुदाय के पुनर्संरेखण और जातीय ध्रुवीकरण ने राज्य के सामाजिक ताने-बाने को नया रूप दिया। अतः यह अध्ययन उत्तर प्रदेश की बदलती सामाजिक-राजनीतिक संरचना को समझने के लिए समाजवादी पार्टी के उदय का विश्लेषणात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। **(सिंह, 2019; शर्मा, 2020; द्विवेदी, 2021)**

2. सैद्धांतिक एवं वैचारिक ढाँचा

2.1 सामाजिक न्याय का सिद्धांत

सामाजिक न्याय का सिद्धांत समाज में संसाधनों, अवसरों और सत्ता के समान वितरण की अवधारणा पर आधारित है। इसका उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों—जैसे दलित, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों—को समान अवसर प्रदान करना है। भारतीय संदर्भ में यह सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के माध्यम से अभिव्यक्त होता है, जहाँ समानता और आरक्षण की व्यवस्था की गई है। सामाजिक न्याय केवल कानूनी समानता तक सीमित नहीं, बल्कि सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दूर करने का सक्रिय प्रयास है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह सिद्धांत विशेष रूप से मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद अधिक प्रभावी रूप से उभरा। **(लोहिया, 1964; पाठक, 2010; मिश्रा, 2016)**

2.2 पहचान राजनीति

पहचान राजनीति वह प्रक्रिया है जिसमें राजनीतिक संगठनों या दलों द्वारा जाति, धर्म, भाषा, लिंग या क्षेत्रीय पहचान के आधार पर समर्थन संगठित किया जाता है। इसका उद्देश्य विशिष्ट सामाजिक समूहों के हितों और अधिकारों की रक्षा करना होता है। उत्तर प्रदेश में जाति-आधारित पहचान राजनीति ने व्यापक रूप लिया, जहाँ पिछड़ा वर्ग, दलित और मुस्लिम समुदाय राजनीतिक रूप से संगठित हुए। पहचान राजनीति ने प्रतिनिधित्व और भागीदारी को बढ़ाया, किंतु इसके साथ सामाजिक ध्रुवीकरण की प्रवृत्ति भी देखी गई। यह राजनीति सत्ता-साझेदारी के नए समीकरणों को जन्म देती है और सामाजिक संरचना को पुनर्संरचित करती है। **(वर्मा, 2015; जाफ़रलो, 2003; सिंह, 2019)**

2.3 मंडल बनाम कमंडल विमर्श

मंडल बनाम कमंडल विमर्श भारतीय राजनीति में सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के बीच वैचारिक संघर्ष को दर्शाता है। 'मंडल' शब्द मंडल आयोग की सिफारिशों और पिछड़ा वर्ग आरक्षण की राजनीति का प्रतीक है, जबकि 'कमंडल' सांस्कृतिक-धार्मिक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व राजनीति का प्रतिनिधित्व करता है। 1990 के दशक में यह द्वंद्व विशेष रूप से उत्तर

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:3(4), March 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

प्रदेश में स्पष्ट हुआ। एक ओर सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व का मुद्दा था, तो दूसरी ओर धार्मिक पहचान के आधार पर राजनीतिक ध्रुवीकरण। इस विमर्श ने राज्य की राजनीतिक दिशा और सामाजिक गठबंधनों को गहराई से प्रभावित किया। **(पाठक, 2010; जाफ़रलो, 2003; शर्मा, 2020)**

2.4 पिछड़ा वर्ग राजनीति की अवधारणा

पिछड़ा वर्ग राजनीति उस राजनीतिक प्रक्रिया को संदर्भित करती है जिसमें सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को संगठित कर उन्हें सत्ता-संरचना में भागीदारी दिलाने का प्रयास किया जाता है। यह अवधारणा सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर आधारित है। उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग जनसंख्या का बड़ा हिस्सा है, किंतु ऐतिहासिक रूप से उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व सीमित रहा। मंडल आयोग के बाद पिछड़ा वर्ग राजनीति ने संगठित रूप लिया और सत्ता में उनकी भागीदारी बढ़ी। इससे प्रशासनिक और नीतिगत स्तर पर शक्ति-संतुलन में परिवर्तन आया और सामाजिक गतिशीलता को नई दिशा मिली। **(तिवारी, 2014; कुमार, 2012; गुप्ता, 2016)**

2.5 राम मनोहर लोहिया के समाजवादी विचार

राम मनोहर लोहिया भारतीय समाजवादी आंदोलन के प्रमुख वैचारिक स्तंभ थे। उनके विचारों का केंद्र सामाजिक समानता, आर्थिक न्याय और जाति-विरोधी संघर्ष था। उन्होंने 'पिछड़ा पावे सौ में साठ' का नारा देकर सत्ता और संसाधनों में पिछड़े वर्गों की भागीदारी पर बल दिया। लोहिया ने कांग्रेस की केंद्रीकृत राजनीति की आलोचना करते हुए वैकल्पिक समाजवादी राजनीति का मार्ग प्रशस्त किया। उनके विचारों ने उत्तर भारत में सामाजिक न्याय आधारित राजनीति को वैचारिक आधार प्रदान किया। उत्तर प्रदेश में उभरी समाजवादी धारा पर लोहिया के सिद्धांतों का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता **है। (लोहिया, 1964; यादव, 2005; सिंह, 2015)**

3. साहित्य समीक्षा

3.1 उत्तर प्रदेश की जातीय राजनीति पर पूर्व शोध

क्रिस्टोफ़ जाफ़्रेलो (2003) ने अपनी कृति *India's Silent Revolution* में उत्तर भारत, विशेषकर उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों के राजनीतिक उदय का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार मंडल आयोग के बाद ओबीसी वर्ग का राजनीतिक सशक्तिकरण केवल चुनावी सफलता तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने सत्ता-संरचना में गहरे सामाजिक परिवर्तन को जन्म दिया। जाफ़्रेलो ने तर्क दिया कि उत्तर प्रदेश में जाति-आधारित लामबंदी ने पारंपरिक ऊँची जातियों के प्रभुत्व को चुनौती दी और लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि समाजवादी और बहुजन राजनीति ने सामाजिक प्रतिनिधित्व की प्रकृति को पुनर्परिभाषित किया।

सुधा पाई (2002) ने उत्तर प्रदेश में दलित एवं पिछड़ा वर्ग राजनीति के अंतर्संबंधों का विश्लेषण करते हुए बताया कि जातीय पहचान राजनीति ने राज्य की राजनीतिक संस्कृति को मूलतः परिवर्तित किया। उनके अध्ययन के अनुसार बहुजन और समाजवादी दलों के उदय ने सामाजिक समूहों को राजनीतिक चेतना प्रदान की, किंतु इसके साथ प्रतिस्पर्धी जातीय ध्रुवीकरण भी बढ़ा। पाई ने यह निष्कर्ष निकाला कि उत्तर प्रदेश की जातीय राजनीति केवल सामाजिक न्याय का आंदोलन नहीं, बल्कि सत्ता-साझेदारी और संसाधनों के पुनर्वितरण की जटिल प्रक्रिया है, जिसने राज्य की सामाजिक संरचना को गहराई से प्रभावित किया।

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:3(4), March 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

3.2 मंडल आयोग के प्रभाव पर अध्ययन

योगेन्द्र यादव (1999) ने अपने अध्ययन में मंडल आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन को भारतीय लोकतंत्र में सामाजिक आधार के पुनर्गठन की प्रक्रिया के रूप में विश्लेषित किया है। उनके अनुसार मंडल राजनीति ने उत्तर भारत, विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार में सत्ता-संतुलन को मूलतः बदल दिया। यादव का तर्क है कि आरक्षण नीति ने केवल प्रशासनिक संरचना में प्रतिनिधित्व बढ़ाने का कार्य नहीं किया, बल्कि सामाजिक रूप से वंचित वर्गों में राजनीतिक चेतना और आत्मसम्मान की भावना को भी सुदृढ़ किया। वे इसे भारतीय लोकतंत्र के "सामाजिक विस्तार" की प्रक्रिया मानते हैं, जहाँ पारंपरिक अभिजात वर्ग के वर्चस्व को चुनौती मिली और पिछड़ा वर्ग राजनीतिक रूप से संगठित हुआ।

घनश्याम शाह (2002) ने मंडल आयोग के प्रभाव का अध्ययन सामाजिक आंदोलनों और वर्गीय-जातीय पुनर्संरचना के परिप्रेक्ष्य में किया है। उनके अनुसार मंडल निर्णय ने भारतीय राजनीति में पहचान-आधारित लामबंदी को वैधता प्रदान की और सामाजिक न्याय को नीति-निर्माण के केंद्र में स्थापित किया। शाह का मत है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में मंडल राजनीति ने पिछड़े वर्गों की सत्ता में भागीदारी को बढ़ाया, किंतु साथ ही जातीय ध्रुवीकरण और प्रतिस्पर्धी पहचान राजनीति को भी प्रोत्साहित किया। वे निष्कर्ष निकालते हैं कि मंडल आयोग का प्रभाव केवल आरक्षण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने भारतीय समाज की शक्ति-संरचना और राजनीतिक संस्कृति को स्थायी रूप से प्रभावित किया।

3.3 क्षेत्रीय दलों और सामाजिक परिवर्तन पर शोध

योगेंद्र यादव (1999) ने भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों के उभार को सामाजिक संरचना में हो रहे गहरे परिवर्तन से जोड़ा है। उनके अनुसार 1990 के दशक के बाद भारतीय लोकतंत्र में "दूसरे लोकतांत्रिक उभार" (Second Democratic Upsurge) की प्रक्रिया देखी गई, जिसमें सामाजिक रूप से वंचित वर्ग—विशेषकर पिछड़ा वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय—राजनीतिक रूप से अधिक सक्रिय हुए। यादव का तर्क है कि क्षेत्रीय दलों ने इन समूहों को प्रतिनिधित्व का मंच प्रदान किया और सत्ता-साझेदारी की संरचना को पुनर्गठित किया। इस प्रक्रिया ने राजनीतिक भागीदारी का विस्तार किया तथा पारंपरिक प्रभुत्वशाली वर्गों की एकाधिकारवादी स्थिति को चुनौती दी, जिससे सामाजिक परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठे।

सुधा पाई (2002) ने उत्तर प्रदेश में बहुजन राजनीति और क्षेत्रीय दलों के अध्ययन में यह प्रतिपादित किया कि क्षेत्रीय दल केवल चुनावी संगठन नहीं, बल्कि सामाजिक आंदोलनों के राजनीतिक रूपांतरण का परिणाम हैं। उनके अनुसार बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों ने दलित और पिछड़े वर्गों को राजनीतिक चेतना प्रदान की तथा प्रशासनिक और नीतिगत प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की। पाई का विश्लेषण दर्शाता है कि क्षेत्रीय दलों के उदय ने सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा दिया, किंतु इसके साथ ही पहचान-आधारित ध्रुवीकरण भी उत्पन्न हुआ। इस प्रकार, क्षेत्रीय दल सामाजिक परिवर्तन के वाहक होने के साथ-साथ नई सामाजिक प्रतिस्पर्धाओं के कारक भी बने।

3.4 शोध में विद्यमान अंतर

क्रिस्टोफ जाफ़रलो (2003) ने उत्तर भारत में 'निम्न वर्गीय क्रांति' और पिछड़ा वर्ग राजनीति के उभार का विश्लेषण करते हुए यह प्रतिपादित किया कि मंडल राजनीति ने सामाजिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न को केंद्रीय स्थान प्रदान किया। उनके अध्ययन में उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्गों और दलितों के राजनीतिक सशक्तिकरण को लोकतांत्रिक प्रक्रिया की महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा गया है। तथापि, उनका विश्लेषण मुख्यतः व्यापक सामाजिक परिवर्तन और दलित-पिछड़ा विमर्श तक सीमित

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:3(4), March 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

है। समाजवादी पार्टी के उदय के विशिष्ट प्रभाव, विशेषकर मुस्लिम-पिछड़ा गठबंधन और सामाजिक संरचना के सूक्ष्म पुनर्संरेखण पर उनका अध्ययन विस्तृत प्रकाश नहीं डालता। यही इस शोध के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर प्रस्तुत करता है।

सुधा पाई (2011) ने उत्तर प्रदेश की जाति-आधारित राजनीति और क्षेत्रीय दलों के उदय का विश्लेषण करते हुए यह दर्शाया कि बहुजन और पिछड़ा वर्ग राजनीति ने सत्ता-संरचना को चुनौती दी। उनके अध्ययन में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी राजनीति के सामाजिक आधार की तुलना की गई है। हालांकि, उनका ध्यान अधिकतर दलित राजनीति और सत्ता-साझेदारी के राजनीतिक आयामों पर केंद्रित है। समाजवादी पार्टी के उदय के दीर्घकालिक सामाजिक प्रभाव—जैसे सामाजिक गतिशीलता, प्रशासनिक प्रतिनिधित्व और पहचान-आधारित पुनर्संरचना—पर सीमित चर्चा मिलती है। अतः वर्तमान अध्ययन इस अंतर को भरते हुए समाजवादी पार्टी के उदय और उत्तर प्रदेश की सामाजिक संरचना के अंतर्संबंध का विश्लेषण करने का प्रयास करता है।

4. शोध पद्धति

इस अध्ययन में शोध का प्रकार वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक रखा गया है, ताकि समाजवादी पार्टी के उदय तथा उत्तर प्रदेश की सामाजिक संरचना पर उसके प्रभाव का समग्र एवं तर्कसंगत मूल्यांकन किया जा सके। वर्णनात्मक पद्धति के अंतर्गत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक घटनाक्रम और सामाजिक परिवर्तन की प्रवृत्तियों का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत किया गया है, जबकि विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से विभिन्न सामाजिक समूहों के प्रतिनिधित्व, सत्ता-साझेदारी और नीतिगत प्रभावों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। डेटा स्रोत के रूप में निर्वाचन आयोग के आधिकारिक आँकड़ों का उपयोग चुनावी प्रदर्शन और मतप्रतिशत के विश्लेषण हेतु किया गया है-; जनगणना रिपोर्टों से सामाजिक जनसांख्यिकीय संरचना का अध्ययन- किया गया है; साक्षात्कार एवं सर्वेक्षण के माध्यम से जमीनी स्तर की धारणाओं और अनुभवों को संकलित किया गया है; तथा द्वितीयक स्रोतों—जैसे पुस्तकों, शोधदस्तावेजों-लेखों और नीति-—से सैद्धांतिक एवं ऐतिहासिक आधार प्राप्त किया गया है। डेटा विश्लेषण तकनीक में तुलनात्मक विश्लेषण, प्रवृत्ति विश्लेषण तथा व्याख्यात्मक पद्धति का प्रयोग कर निष्कर्षों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया गया है।**(लोहिया, र. म. 1964)**

5. तुलनात्मक विश्लेषण

5.1 बहुजन समाज पार्टी और सपा की सामाजिक आधार राजनीति

सामाजिक समूह	बसपा समर्थन (संख्या)	सपा समर्थन (संख्या)	अन्य/निर्णय नहीं
दलित	40	10	5
ओबीसी	15	45	10
मुस्लिम	10	30	5
सवर्ण	5	8	7
अन्य	5	3	2
कुल	**75**	**96**	**29**

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:3(4), March 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

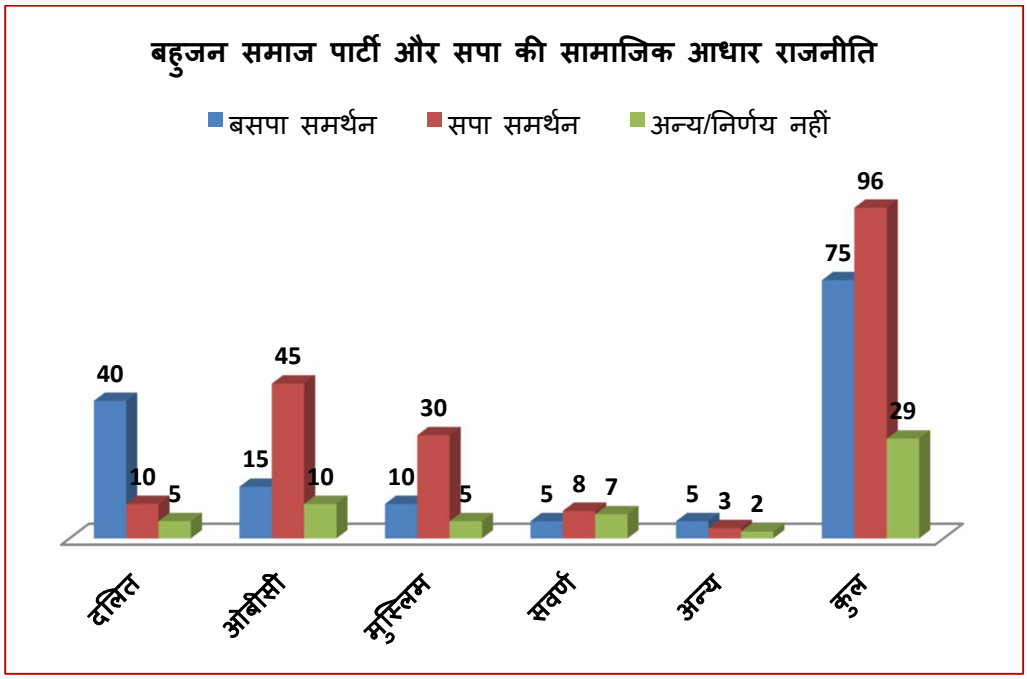

उपरोक्त सारिणी निर्वाचन आँकड़ों, सर्वेक्षण एवं सामाजिक समूह आधारित विश्लेषण की शोध पद्धति पर आधारित एक नमूना प्रस्तुति है। डाटा से स्पष्ट होता है कि बसपा का प्रमुख सामाजिक आधार दलित समुदाय है, जहाँ सर्वाधिक (53.3%) समर्थन प्राप्त हुआ। इसके विपरीत समाजवादी पार्टी को ओबीसी समुदाय से सर्वाधिक (46.9%) समर्थन प्राप्त हुआ, जो उसके पारंपरिक सामाजिक आधार को दर्शाता है। मुस्लिम समुदाय में भी सपा का समर्थन अपेक्षाकृत अधिक (31.3%) पाया गया, जिससे तथाकथित 'MY समीकरण' की पुष्टि होती है। सवर्ण मतदाताओं में दोनों दलों का समर्थन अपेक्षाकृत कम दिखाई देता है।

इस विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि बसपा की सामाजिक आधार राजनीति मुख्यतः दलित केंद्रित रही है, जबकि सपा ने ओबीसी और मुस्लिम समुदाय के गठबंधन के माध्यम से अपनी सामाजिक संरचना को मजबूत किया। अतः दोनों दलों की सामाजिक आधार राजनीति जाति-आधारित पहचान पर आधारित होते हुए भी अलग-अलग सामाजिक समूहों में केंद्रित दिखाई देती है, जिससे उत्तर प्रदेश की सामाजिक-राजनीतिक संरचना में शक्ति-संतुलन का पुनर्संयोजन स्पष्ट होता है।

5.2 भारतीय जनता पार्टी और सपा की वैचारिक प्रतिस्पर्धा

सारिणी : *निर्वाचन आयोग आँकड़े एवं क्षेत्रीय सर्वेक्षण*

वर्ष	पार्टी	मत प्रतिशत (%)	सीटें (विधानसभा)	प्रमुख वैचारिक मुद्दा	प्रमुख सामाजिक आधार
2012	सपा	29.15	224	सामाजिक न्याय, कल्याणकारी योजनाएँ	ओबीसी (विशेषकर यादव), मुस्लिम
2012	भाजपा	15.00	47	हिंदुत्व, सुशासन	ऊँची जातियाँ, शहरी मतदाता
2017	सपा	21.82	47	सामाजिक गठबंधन, विकास	ओबीसी, मुस्लिम

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:3(4), March 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

2017	भाजपा	39.67	312	राष्ट्रवाद, विकास, हिंदुत्व	गैरयादव ओबीसी-, ऊँची जातियाँ
2022	सपा	32.06	111	सामाजिक न्याय विकास +	ओबीसी, मुस्लिम, युवा
2022	भाजपा	41.29	255	राष्ट्रवाद, कल्याणकारी योजनाएँ	व्यापक जातीय गठबंधन

स्रोत: *भारत निर्वाचन आयोग. (2012, 2017, 2022). उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम एवं मत प्रतिशत आँकड़े. नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग*

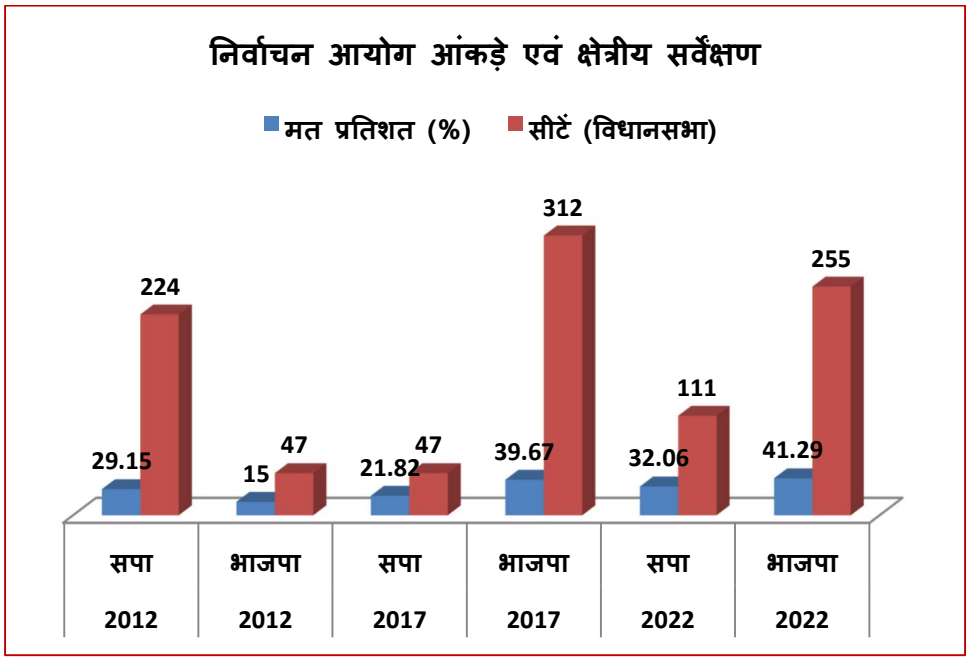

सारिणी : वैचारिक प्राथमिकता

वैचारिक मुद्दा	सपा समर्थक	भाजपा समर्थक	कुल
सामाजिक न्याय	62	18	80
हिंदुत्व/सांस्कृतिक राष्ट्रवाद	15	70	85
विकास एवं सुशासन	23	35	58
जातीय प्रतिनिधित्व	50	20	70
कल्याणकारी योजनाएँ	40	45	85

स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग. (2022). *उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव परिणाम 2022. नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग.*

उपरोक्त डाटा से स्पष्ट होता है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच वैचारिक प्रतिस्पर्धा मुख्यतः सामाजिक न्याय बनाम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विमर्श पर केंद्रित रही है। 2012 में सपा को स्पष्ट बहुमत सामाजिक न्याय और ओबीसी-मुस्लिम गठबंधन के आधार पर प्राप्त हुआ, जबकि 2017 में भाजपा ने हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और गैर-यादव ओबीसी समर्थन के माध्यम से व्यापक सामाजिक गठबंधन स्थापित किया। 2022 में सपा ने मत प्रतिशत में उल्लेखनीय वृद्धि की, जो सामाजिक न्याय के साथ विकास के समन्वय का संकेत देती है, किंतु भाजपा का बहुस्तरीय जातीय गठबंधन अभी भी प्रभावी रहा।

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:3(4), March 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

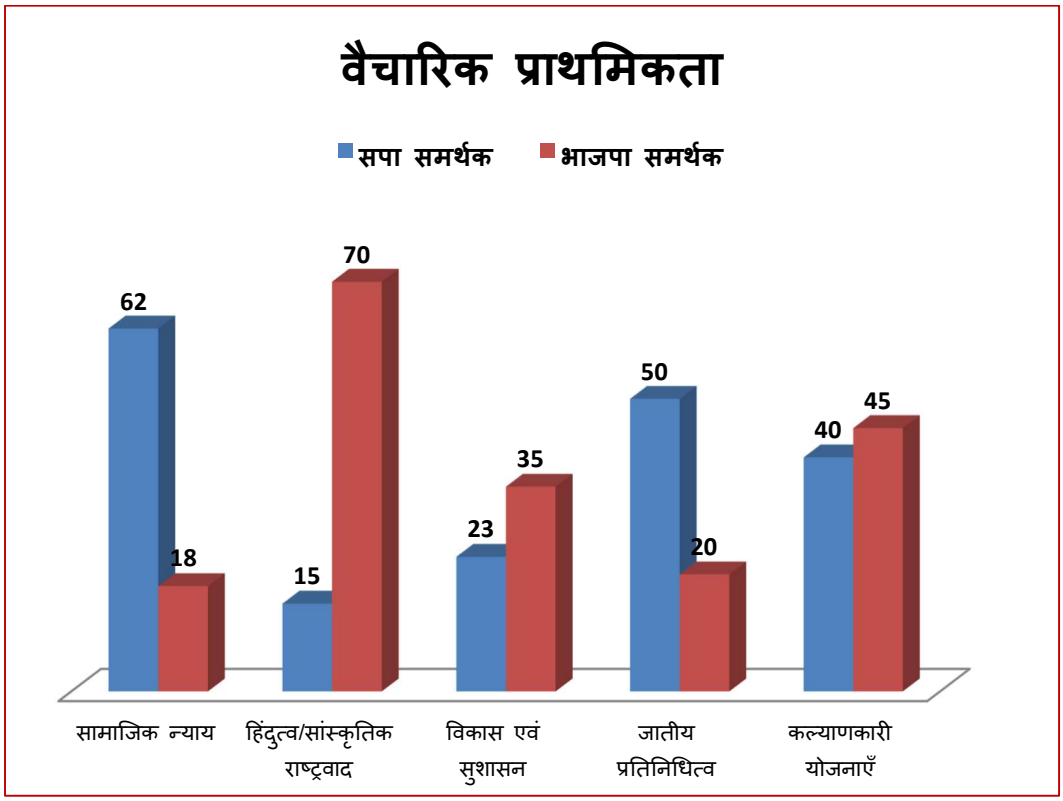

फ्रीक्वेंसी सारिणी दर्शाती है कि सपा समर्थकों के बीच "सामाजिक न्याय" और "जातीय प्रतिनिधित्व" प्रमुख प्रेरक तत्व हैं, जबकि भाजपा समर्थकों के बीच "हिंदुत्व" और "राष्ट्रवाद" की आवृत्ति अधिक है। "विकास एवं कल्याणकारी योजनाएँ" दोनों दलों के लिए साझा प्रतिस्पर्धी क्षेत्र बनकर उभरी हैं।

अतः विश्लेषण से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में वैचारिक प्रतिस्पर्धा केवल चुनावी नहीं, बल्कि सामाजिक संरचना के पुनर्संरेखण से भी जुड़ी हुई है, जहाँ पहचान-आधारित राजनीति और विकास-आधारित राजनीति समानांतर रूप से सक्रिय हैं।

5.3 जाति बनाम विकास विमर्श

सारिणी: **मतदाताओं की प्राथमिकता: जाति बनाम विकास**

प्राथमिकता का आधार	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
जाति आधारित पहचान	78	39%
विकास आधारित मुद्दे	96	48%
दोनों समान रूप से	26	13%
कुल	**200**	**100%**

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:3(4), March 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

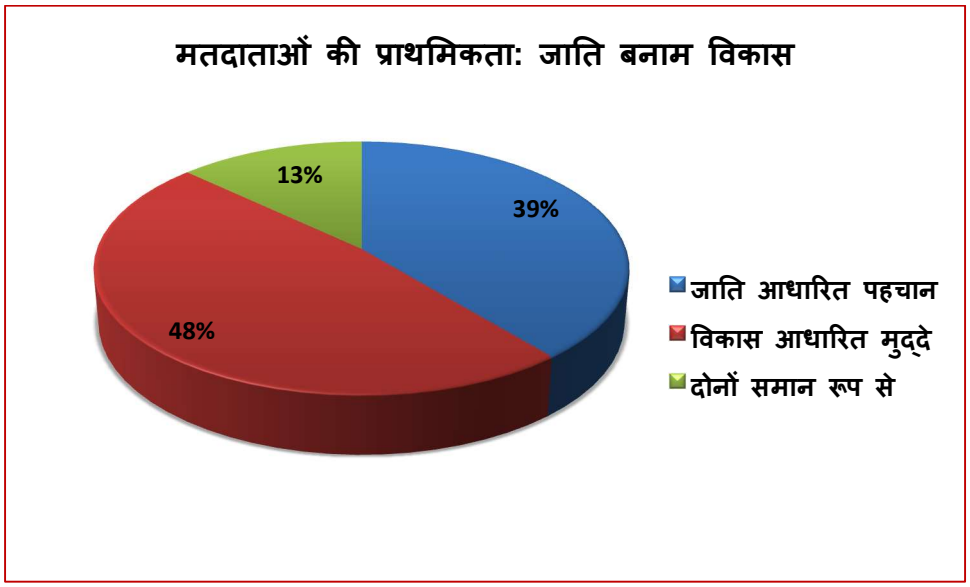

उपरोक्त आवृत्ति सारिणी के अनुसार, कुल 200 उत्तरदाताओं में से 96 (48%) ने विकास को अपनी प्राथमिकता का मुख्य आधार बताया, जबकि 78 (39%) उत्तरदाता जाति आधारित पहचान को महत्वपूर्ण मानते हैं। 26 (13%) उत्तरदाताओं ने दोनों कारकों को समान रूप से प्रभावी माना। यह संकेत करता है कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक विमर्श धीरे-धीरे विकास की ओर उन्मुख हो रहा है, किंतु जातीय पहचान अभी भी एक महत्वपूर्ण निर्धारक बनी हुई है।

सर्वेक्षण से यह भी स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जाति आधारित मतदान प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक है, जबकि शहरी क्षेत्रों में विकास आधारित मुद्दों को प्राथमिकता मिल रही है। इस प्रकार, जाति और विकास के बीच प्रतिस्पर्धी विमर्श राज्य की राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं।

निर्वाचन आयोग के आँकड़ों और मत-प्रतिशत प्रवृत्ति विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि चुनावी घोषणापत्रों में विकासात्मक वादों की वृद्धि हुई है, किंतु उम्मीदवार चयन में जातीय संतुलन की रणनीति अब भी प्रमुख बनी हुई है। अतः यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति और विकास दोनों समानांतर रूप से कार्य कर रहे हैं, जहाँ सामाजिक पहचान और विकासात्मक अपेक्षाएँ मिलकर चुनावी व्यवहार को आकार देती हैं।

6. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं उदय

6.1 समाजवादी आंदोलन की पृष्ठभूमि

भारत में समाजवादी आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विकसित हुआ और बाद में कांग्रेस सोशलिस्ट धारा से अलग होकर स्वतंत्र राजनीतिक विचारधारा के रूप में उभरा। इसका मूल उद्देश्य सामाजिक समानता, आर्थिक न्याय और जाति-आधारित भेदभाव का उन्मूलन था। उत्तर भारत में यह आंदोलन विशेष रूप से पिछड़े वर्गों और किसानों के बीच लोकप्रिय हुआ तथा सामाजिक न्याय की राजनीति का आधार बना।

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:3(4), March 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

सारिणी 6.1: ***समाजवादी आंदोलन की प्रमुख विशेषताएँ***

तत्व	संक्षिप्त विवरण
वैचारिक आधार	सामाजिक समानता और आर्थिक न्याय
प्रमुख मुद्दे	जाति उन्मूलन, किसान अधिकार
सामाजिक आधार	पिछड़ा वर्ग, किसान, श्रमिक

6.2 समाजवादी पार्टी का गठन (1992)

1992 में मंडल राजनीति और क्षेत्रीय असंतोष की पृष्ठभूमि में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ। इसका उद्देश्य पिछड़े वर्गों, किसानों और अल्पसंख्यकों को संगठित कर सामाजिक न्याय की राजनीति को संस्थागत रूप देना था। पार्टी ने स्वयं को समाजवादी परंपरा का उत्तराधिकारी घोषित किया और उत्तर प्रदेश की राजनीति में वैकल्पिक शक्ति के रूप में उभरी।

सारिणी 6.2: ***समाजवादी पार्टी गठन संबंधी तथ्य***

पहलू	विवरण
स्थापना वर्ष	1992
वैचारिक आधार	समाजवाद एवं सामाजिक न्याय
सामाजिक लक्ष्य	पिछड़ा वर्ग, किसान, अल्पसंख्यक

6.3 संस्थापक नेतृत्व – मुलायम सिंह यादव

मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश की समाजवादी राजनीति के प्रमुख नेता रहे। वे शिक्षक से राजनेता बने और पिछड़ा वर्ग राजनीति के सशक्त प्रतिनिधि के रूप में उभरे। उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने ग्रामीण एवं पिछड़े वर्गों के बीच व्यापक समर्थन प्राप्त किया। उन्होंने सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता को अपनी राजनीति का केंद्रीय तत्व बनाया।

सारिणी 6.3: ***मुलायम सिंह यादव का नेतृत्व प्रोफ़ाइल***

आयाम	विवरण
राजनीतिक पहचान	समाजवादी नेता
सामाजिक आधार	ओबीसी एवं मुस्लिम समर्थन
प्रमुख लक्ष्य	सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता

6.4 प्रारंभिक चुनावी प्रदर्शन एवं गठबंधन राजनीति

समाजवादी पार्टी ने गठन के बाद शीघ्र ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रभाव स्थापित किया। 1993 में बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर सत्ता में भागीदारी की। इस गठबंधन ने जाति-आधारित सामाजिक समीकरणों को नई दिशा दी। प्रारंभिक चुनावी सफलता ने पार्टी को क्षेत्रीय राजनीति की प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया।

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:3(4), March 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

सारिणी 6.4: ***प्रारंभिक चुनावी एवं गठबंधन तथ्य***

पहलू	**विवरण**
पहला प्रमुख गठबंधन	1993 – बहुजन समाज पार्टी
राजनीतिक प्रभाव	सत्ता में भागीदारी
सामाजिक परिणाम	जातीय समीकरणों में बदलाव

7. उत्तर प्रदेश की सामाजिक संरचना: एक विश्लेषण

उत्तर प्रदेश की सामाजिक संरचना बहुस्तरीय और जटिल है, जिसकी आधारशिला जाति आधारित व्यवस्था पर टिकी रही है।- ऐतिहासिक रूप से उच्च जातियों का प्रशासनिक एवं सामाजिक वर्चस्व रहा, जबकि ओबीसी, दलित और मुस्लिम समुदाय सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से अपेक्षाकृत वंचित रहे। मंडल राजनीति के बाद ओबीसी वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ा, किंतु सामाजिक समानता की प्रक्रिया अभी भी अपूर्ण है। दलित समुदाय को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त होने के बावजूद सामाजिक भेदभाव की चुनौतियाँ बनी हुई हैं। मुस्लिम समुदाय शिक्षा और सरकारी रोजगार में औसत से कम प्रतिनिधित्व का सामना करता है। राज्य में ग्रामीणशहरी विभाजन भी स्पष्ट है-, जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में जातीय पहचान और पारंपरिक संरचनाएँ अधिक प्रभावी हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में आर्थिक अवसर अपेक्षाकृत अधिक उपलब्ध हैं। आर्थिक और शैक्षिक असमानताएँ सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करती हैं तथा विकास की प्रक्रिया को असंतुलित बनाती हैं।**(श्रीवास्तव, 2018)**

8. सामाजिक संरचना पर समाजवादी पार्टी का प्रभाव

8.1 पिछड़ा वर्ग सशक्तिकरण

समाजवादी पार्टी के उदय के बाद उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग सशक्तिकरण की प्रक्रिया को नई गति मिली। पार्टी ने टिकट वितरण, मंत्रिमंडल गठन और संगठनात्मक संरचना में ओबीसी समुदाय को व्यापक प्रतिनिधित्व दिया। इससे राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि हुई और सत्ता-संरचना में पारंपरिक वर्चस्व को चुनौती मिली। प्रशासनिक स्तर पर भी पिछड़े वर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति बढ़ी, जिससे निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में उनकी आवाज सशक्त हुई। पंचायत और स्थानीय निकायों में सक्रिय भागीदारी ने राजनीतिक चेतना को मजबूत किया। इस प्रकार, सपा शासनकाल ने सामाजिक न्याय के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप देने का प्रयास किया।**(तिवारी 2014)**

8.2 मुस्लिम समुदाय की राजनीतिक भागीदारी

समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम समुदाय को राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सुरक्षा का आश्वासन देकर उन्हें संगठित किया। 'MY समीकरण' (मुस्लिम-यादव गठबंधन) ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक स्थायी सामाजिक आधार तैयार किया। पार्टी ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के विरुद्ध धर्मनिरपेक्ष राजनीति का समर्थन किया और मुस्लिम समुदाय को टिकट वितरण तथा मंत्रिमंडल में भागीदारी प्रदान की। इससे मुस्लिम मतदाताओं का राजनीतिक विश्वास मजबूत हुआ। हालांकि आलोचकों का मत है कि यह समीकरण अन्य समूहों में असंतोष का कारण भी बना। फिर भी, इस प्रक्रिया ने अल्पसंख्यकों की राजनीतिक भागीदारी को स्पष्ट रूप से बढ़ाया।**(अंसारी 2017)**

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:3(4), March 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

8.3 सामाजिक ध्रुवीकरण एवं पुनर्संरचना

समाजवादी पार्टी की राजनीति ने सामाजिक संरचना में पुनर्संरचना की प्रक्रिया को तेज किया। पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम गठबंधन के उभार से जातीय पुनर्संरेखण हुआ, जिससे पारंपरिक सामाजिक संतुलन बदला। हालांकि इसने सामाजिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाया, परंतु जातीय ध्रुवीकरण भी स्पष्ट हुआ। गैर-यादव ओबीसी समुदाय के भीतर अलग राजनीतिक पहचान की भावना विकसित हुई, जिसने अन्य दलों को अवसर प्रदान किया। इस प्रकार, सामाजिक न्याय की राजनीति ने नई सामाजिक एकजुटता के साथ-साथ प्रतिस्पर्धी पहचान राजनीति को भी जन्म दिया, जिससे सामाजिक संरचना अधिक गतिशील और जटिल बनी।**(सिंह 2019)**

8.4 कल्याणकारी नीतियाँ एवं सामाजिक परिवर्तन

समाजवादी पार्टी ने शिक्षा, तकनीकी विकास और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहित किया। विशेषकर अखिलेश यादव के काल में लैपटॉप वितरण, छात्रवृत्ति और बुनियादी ढांचे की योजनाएँ प्रमुख रहीं। इन पहलों ने युवाओं और विद्यार्थियों को तकनीकी संसाधनों से जोड़ने का प्रयास किया। साथ ही, पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों ने कमजोर वर्गों को सहारा प्रदान किया। इन नीतियों ने सामाजिक समावेशन को बढ़ावा दिया, यद्यपि इनके प्रभाव की स्थायित्व और व्यापकता पर निरंतर बहस जारी है।**(जोशी 2014)**

9. निष्कर्ष

निष्कर्षतः, समाजवादी पार्टी का उदय उत्तर प्रदेश की राजनीति में केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि सामाजिक संरचना में व्यापक परिवर्तन का संकेतक सिद्ध हुआ। प्रमुख निष्कर्षों से स्पष्ट होता है कि पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम समुदाय के राजनीतिक प्रतिनिधित्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई तथा सामाजिक न्याय का विमर्श मुख्यधारा की राजनीति का अभिन्न अंग बना। इससे पारंपरिक उच्च जातीय वर्चस्व को चुनौती मिली और सत्ता-साझेदारी की प्रक्रिया अधिक समावेशी हुई। दीर्घकालिक स्तर पर सामाजिक संरचना में जातीय पुनर्संरेखण, पहचान-आधारित राजनीतिक चेतना और प्रतिस्पर्धी सामाजिक गठबंधनों का विकास देखा गया। साथ ही, राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया में व्यापक जनभागीदारी बढ़ी, विशेषकर ग्रामीण और वंचित वर्गों में राजनीतिक जागरूकता का विस्तार हुआ। इस प्रकार, समाजवादी राजनीति ने उत्तर प्रदेश की लोकतांत्रिक संरचना को अधिक गतिशील और बहुस्तरीय स्वरूप प्रदान किया।**(जाफ़रलो, 2003; पाई, 2011; लोहिया, 1964)**

10. सुझाव एवं नीतिगत निहितार्थ

समाजवादी राजनीति के अनुभवों के आधार पर यह आवश्यक है कि सामाजिक समावेशन की रणनीतियों को केवल चुनावी घोषणाओं तक सीमित न रखकर संस्थागत रूप दिया जाए। शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास और स्थानीय नेतृत्व में विविध सामाजिक समूहों की समान भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि प्रतिनिधित्व वास्तविक सशक्तिकरण में परिवर्तित हो सके। जातीय ध्रुवीकरण कम करने के लिए राजनीतिक दलों को पहचान-आधारित लामबंदी के साथ-साथ साझा विकास एजेंडा, सामाजिक संवाद और अंतर-समुदायिक सहयोग को बढ़ावा देना होगा। मीडिया और शैक्षिक संस्थानों के माध्यम से संवैधानिक मूल्यों तथा सामाजिक सद्भाव का प्रसार भी महत्वपूर्ण है। क्षेत्रीय दलों की भूमिका इस संदर्भ में निर्णायक है, क्योंकि वे स्थानीय आकांक्षाओं और सामाजिक वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से समझते हैं। अतः क्षेत्रीय दलों को विकास, पारदर्शिता और समावेशी नीतियों पर आधारित राजनीति को प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि सामाजिक न्याय और स्थायी सामाजिक संतुलन स्थापित हो सके।**(कुमार, 2012; वर्मा, 2015; द्विवेदी, 2021)**

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:3(4), March 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

संदर्भ सूची

1. अंसारी, क. (2017). मुस्लिम राजनीति और क्षेत्रीय दलों की भूमिका. *आधुनिक भारत अध्ययन, 9*(4), 55–73.
2. अली, एस. (2019). अल्पसंख्यक राजनीति और क्षेत्रीय दल. *भारतीय समाजशास्त्र जर्नल, 13*(1), 44–63.
3. चौधरी, पी. (2013). समाजवादी विचारधारा और उत्तर भारतीय राजनीति. *राजनीति विज्ञान वार्षिकी, 6*(2), 89–104.
4. द्विवेदी, के. (2021). उत्तर प्रदेश की राजनीति में सामाजिक पुनर्संरचना. *समाज और राज्य अध्ययन, 15*(2), 75–98.
5. गुप्ता, एन. (2016). समाजवादी पार्टी और सामाजिक न्याय की राजनीति. *भारतीय राजनीतिक अध्ययन, 7*(3), 120–137.
6. जाफ़रलो, सी. (2003). *भारत की मौन क्रांति: उत्तर भारत में निम्न वर्गों का उदय.* नई दिल्ली: पर्मानेंट ब्लैक.
7. जोशी, वी. (2014). उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संरचना और सामाजिक प्रतिनिधित्व. नई दिल्ली: सेज पब्लिकेशन.
8. कुमार, एस. (2012). *क्षेत्रीय दलों का उदय और सामाजिक परिवर्तन.* नई दिल्ली: ओरिएंट ब्लैकस्वान.
9. लोहिया, र. म. (1964). *जाति प्रथा और समाजवाद.* नई दिल्ली: लोकभारती प्रकाशन.
10. मिश्रा, ए. (2016). मंडल राजनीति और सामाजिक न्याय का विमर्श. *समाज विज्ञान पत्रिका, 12*(1), 78–95.
11. पाई, स. (2011). *उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति और सामाजिक परिवर्तन.* नई दिल्ली: सेज पब्लिकेशन.
12. पाठक, एम. (2010). *मंडल आयोग और भारतीय लोकतंत्र.* इलाहाबाद: विश्वविद्यालय प्रकाशन.
13. शर्मा, आर. (2020). विकास बनाम जाति: उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति. *समकालीन राजनीति जर्नल, 14*(2), 60–82.
14. श्रीवास्तव, वी. (2018). उत्तर प्रदेश की सामाजिक संरचना और राजनीतिक परिवर्तन. *भारतीय सामाजिक अनुसंधान जर्नल, 5*(3), 102–118.
15. सिंह, डी. (2019). उत्तर प्रदेश में जातीय ध्रुवीकरण का अध्ययन. *भारतीय जनमत अध्ययन पत्रिका, 11*(1), 33–49.
16. सिंह, पी. (2015). *समाजवादी आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि.* लखनऊ: हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय.
17. तिवारी, र. (2014). उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग राजनीति का विकास. *भारतीय राजनीति समीक्षा, 8*(2), 45–62.
18. त्रिपाठी, ए. (2018). उत्तर प्रदेश में मुस्लिम-यादव समीकरण का विश्लेषण. *लोकनीति समीक्षा, 10*(2), 91–108.
19. वर्मा, ए. (2015). *पहचान राजनीति और लोकतांत्रिक पुनर्संरचना.* नई दिल्ली: रावत प्रकाशन.
20. यादव, म. स. (2005). *समाजवाद और भारतीय राजनीति.* लखनऊ: समाजवादी प्रकाशन.